सिविल अपील

न्यायमूर्ति आर. एस. नरूला और सी. जी. सूरी के समक्ष

बी एस नाथ , - याचिकाकर्ता

बनाम

बचन सिंह और अन्य, उत्तरदाता।

प्रथम अपील विरुद्ध आदेश संख्या 48/ 1964

2 सितंबर, 1970

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV) - धारा 110 (1), 110A और 110F - मोटर दुर्घटना में हुई संपत्ति का नुकसान या क्षति - क्या केवल सिविल न्यायालयों द्वारा विचार किया जा सकता है - मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण - क्या ऐसे दावों पर निर्णय लेने का अधिकार है - विधियों की व्याख्या - कानून की भाषा जो दो अस्पष्ट व्याख्याओं की ओर ले जाती है - न्यायालय- क्या विधायिका के इरादों का पता लगाने के लिए क़ानून में पूरक प्रावधानों को देखने का हकदार है।

मोटर वाहन अधिनियम 1939 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है, जो मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट से संबंधित दुर्घटनाओं के मामलों में नुकसान का निर्धारण और आदेश देते हैं। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में, जहां भी "चोट या मृत्यु" शब्द होते हैं, उनका उपयोग उसी संदर्भ में किया जाता है और कानूनी अर्थों में 'चोट' शब्द के दायरे को बढ़ाने का इरादा नहीं है ताकि संपत्ति की चोट को शामिल किया जा सके जैसा कि मनुष्यों को चोट या उनकी मृत्यु से अलग है। 'मृत्यु' शब्द के साथ-साथ "चोट" शब्द का उपयोग एक और संकेत है कि केवल शारीरिक चोट कानून के चिंतन के भीतर थी। कानून जो क्षतिपूर्ति करना चाहता है वह दुर्घटना नहीं है, बल्कि परिणामी चोट है। एक घटना या घटना, हालांकि, असामान्य या गंभीर, एक दुर्घटना से कम हो जाएगी यदि इससे कोई चोट नहीं लगती है, चाहे वह किसी व्यक्ति या संपत्ति को हो। यह हमेशा चोट होती है जिसकी भरपाई की जाती है और कानून द्वारा दुर्घटना की भरपाई का कोई सवाल ही नहीं है । 'मुआवजा' शब्द हमेशा उस चोट को योग्य बनाता है जिसकी भरपाई की मांग की जाती है और इस शब्द का दुर्घटना के प्रकार को योग्य बनाने का कोई सवाल नहीं है यह शब्द यह स्पष्ट करता है कि क्षतिपूर्ति की जाने वाली चोट शारीरिक चोट या मृत्यु है और यह अर्थ अधिनियम की धारा 110 ए (एल) द्वारा और स्पष्ट किया गया है जो संपत्ति को नुकसान या चोट के संबंध में किसी भी दावे के मनोरंजन का प्रावधान नहीं करता है। इसलिए मोटर दुर्घटना में संपत्ति के नुकसान या क्षति के दावों पर केवल सिविल न्यायालयों द्वारा विचार किया जा सकता है और अधिनियम के तहत स्थापित दावा न्यायाधिकरणों के पास ऐसे दावों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। (पैरा 15 और 16)

माना जाता है कि विधायिका का कभी भी इरादा नहीं है कि उसकी भाषा दो अर्थों को व्यक्त करेगी या दोहरे निर्माण को स्वीकार करेगी। हालांकि, जहां न्यायालयों को लगता है कि किसी क़ानून द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा दो अस्पष्ट व्याख्याओं को जन्म देती है, तो वे विधायिका के वास्तविक इरादों का पता लगाने के लिए क़ानून में पूरक प्रावधानों को देखने के हकदार होंगे। (पैरा 12)

माननीय न्यायमूर्ति सी जी सूरी द्वारा 4 मई, 1970 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक खंडपीठ को मामला सौंपा गया। इस मामले का निर्णय 2 सितम्बर, 1970 को माननीय न्यायमूर्ति आर एस नरूला और माननीय न्यायमूर्ति सी जी सूरी की खंडपीठ द्वारा किया गया।

श्री गुरचरण सिंह धालीवाल, अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के दिनांक 28 नवम्बर, 1963 के आदेश से नियमित प्रथम अपील, आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा परिकल्पित उचित ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करने के लिए वादी को वापस करना और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ना।

अपीलकर्ता की ओर से जोगिंदर सिंह शाहपुरी, एडवोकेट।

मुनीश्वर पुरी, वकील, उत्तरदाताओं के लिए।

संदर्भ आदेश

न्यायमूर्ति सीजी सूरी, - मोटर दुर्घटना में अपनी कार के नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे के रूप में 2,000 रुपये की वसूली के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर एक वाद को चंडीगढ़ के उप-न्यायाधीश द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **7,** नियम **10** के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण **(**इसके बाद संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल' के रूप में संदर्भित**)** में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया है यह कहते हुए की वह दावे पर विचार करने में सक्षम नहीं है। वादी अपील में आया है।

(2) **3** अक्तूबर**, 1961** को सुबह लगभग **845** बजे अपीलकर्ता की कार नं. पीएनपी**-670** ट्रक नंबर **10** से टकरा गया। चंडीगढ़ राजधानी में सेक्टर **18** और **19** को विभाजित करने वाली सड़क पर पीएनई**-7759**। ट्रक प्रतिवादी नंबर **2** का था और दुर्घटना के समय प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर **1** द्वारा चलाया जा रहा था। यह मेसर्स ओरिएंटल फायर इंश्योरेंस कंपनी, प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर **3** के साथ बीमा किया गया था। अपीलकर्ता को दुर्घटना में न केवल व्यक्तिगत चोटें आईं, बल्कि उसकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपनी व्यक्तिगत चोटों के संबंध में एक अलग दावा दायर किया और बार में यह कहा गया है कि उस दावे को अनुमति दे दी गई है। अपने वाहन को नुकसान के संबंध में, अपीलकर्ता ने सिविल कोर्ट में इस धारणा के तहत एक अलग दावा दायर किया कि ट्रिब्यूनल के पास मोटर दुर्घटना में संपत्ति के नुकसान या क्षति से उत्पन्न मुआवजे के दावे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(3) अदालत के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपत्ति प्रतिवादी-प्रतिवादियों के वकील द्वारा मुद्दों को तैयार करने और मामले के गुण-दोष पर साक्ष्य की जांच करने के बाद ली गई थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा यह दृष्टिकोण लिया गया है कि किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति किसी भी स्तर पर एक पक्ष द्वारा ली जा सकती है और पार्टी को किसी भी छूट या सहमति से उस याचिका को उठाने से नहीं रोका जाता है, मेरे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। अत, मैं इस प्रश्न की जांच करना चाहूंगा कि क्या मुआवजे के लिए ऐसा दावा सिविल न्यायालय में होगा या मोटर यान अधिनियम की धारा **110(1)** के तहत नियुक्त अधिकरण के समक्ष होगा।

(4) संदर्भ की सुविधा के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, **(1939** का **4) (**इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित**)** के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे प्रस्तुत किया गया है**: -**

"धारा **110 (1): -** एक राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण **(**इसके बाद दावा न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित**)** का गठन कर सकती है, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ताकि मृत्यु या शारीरिक चोट से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों पर निर्णय लिया जा सके

(2)* * * *

(3)* * * *

(4)* * * *

धारा **110**क **(1): -** धारा **110** की उपधारा **(1)** में विनिर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है-

a) उस व्यक्ति द्वारा, जिसे चोट लगी है; या

b) जहां मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दुर्घटना से मृत्यु हुई है; नहीं तो

c) घायल व्यक्ति या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी एजेंट द्वारा, जैसा भी मामला हो।

(2) * * * *

(3) * * * *

धारा **110**एफ- जहां किसी क्षेत्र के लिए कोई दावा अधिकरण गठित किया गया है, वहां किसी भी सिविल न्यायालय को मुआवजे के किसी दावे से संबंधित किसी प्रश्न पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा, जिस पर उस क्षेत्र के लिए दावा अधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, और मुआवजे के दावे के संबंध में दावा अधिकरण द्वारा या उसके समक्ष की गई किसी कार्रवाई के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।

उप-न्यायाधीश ने *डॉ. ओम प्रकाश मिश्रा बनाम नेशनल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कं, लिमिटेड और अन्य*, के एक खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहां एक मोटर दुर्घटना व्यक्तिगत चोटों और संपत्ति को नुकसान दोनों का कारण बनती है, जिसे डिवीजन बेंच द्वारा समग्र चोट के मामले के रूप में वर्णित किया गया है, तो पूरे दावे को ट्रिब्यूनल द्वारा सुनवाई योग्य माना जाएगा। उप-न्यायाधीश के आक्षेपित आदेश में निर्णय के प्रासंगिक भागों को पुन: प्रस्तुत किया गया है और चार प्रकार के मामलों पर विचार किया गया है। जहां दुर्घटना व्यक्तिगत चोटों या मृत्यु का कारण बनती है, ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा निश्चित रूप से सक्षम था। इसी प्रकार, ऐसे मामले के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है जहां मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली संपत्ति की हानि ही एकमात्र परिणाम है और इस तरह के दावे पर स्पष्ट रूप से अकेले सिविल न्यायालयों द्वारा विचार किया जा सकता है। एक ऐसा मामला हो सकता है जहां संपत्ति का नुकसान या क्षति हो सकती है, लेकिन उस नुकसान से पीड़ित व्यक्ति को मोटर वाहन अधिनियम की धारा **110** ए के तहत आवेदन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, ऐसे मामलों के संबंध में भी डिवीजन बेंच की राय थी कि सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा और यह आवेदन मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियुक्त ट्रिब्यूनल के पास नहीं होगा। हालांकि, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या में कुछ कठिनाई एक मोटर दुर्घटना के मामले में प्रस्तुत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप समग्र चोटें आई थीं, अर्थात्, दुर्घटना में शामिल व्यक्तियों की शारीरिक चोटें या मृत्यु और मोटर वाहन या अन्य संपत्ति का नुकसान या क्षति। अंतिम निर्णय अधिनियम की धारा **110** की उप-धारा **(1)** में होने वाली "मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों के लिए दावों का अधिनिर्णय" शब्दों की व्याख्या पर बदल गया। न्यायालय की राय थी कि समग्र चोटों के मामलों की चौथी श्रेणी में, अधिनियम की धारा **110 (1)** की सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतुष्ट किया गया था। दावा मुआवजे के लिए था। यह एक दुर्घटना के संबंध में था जिसमें शारीरिक चोट शामिल थी और मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न हुई थी। केवल यह तथ्य कि, इसके अलावा, कार को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया गया था, न्यायालय की राय में, ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है, खासकर जब अधिनियम की धारा **110** एफ मुआवजे के लिए किसी भी दावे से संबंधित सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र को रोकती है, जिस पर ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। अपीलकर्ता का तर्क अदालत के समक्ष प्रबल हुआ, जिसने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुआवजे का दावा करने वाला आवेदन एक दुर्घटना के संबंध में था जिसमें मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न व्यक्ति को शारीरिक चोट शामिल थी। इसके अलावा, वाहन को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया गया था। उस धारा की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसने न्यायालय की राय में किसी अधिकरण को संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में मुआवजे के दावे पर विचार करने से रोक दिया हो, जबकि धारा की अन्य शर्तें भी पूरी तरह से संतुष्ट थीं। न्यायालय ने इस धारा के शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी परिस्थितियों में समग्र चोटों के लिए मुआवजे का दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष सक्षम नहीं होगा। इस धारा में 'मुआवजा' शब्द का पालन किसी भी ऐसी चीज से नहीं किया गया था जो दुर्घटना में लगी दो प्रकार की चोटों में से केवल एक के लिए मुआवजे के पुरस्कार के दायरे को सीमित करे। यदि विधायिका का इरादा ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को सीमित करना था, तो कोई उम्मीद करेगा कि इसे

1 A.I.R. 1962 M.P. 19.

स्पष्ट रूप से कहा जाएगा। 'मुआवजा' शब्द को इतना व्यापक माना गया था कि इसमें व्यक्ति के साथ-साथ वाहनों या अन्य संपत्ति को नुकसान या क्षति शामिल हो। इसके अलावा यह देखा गया कि, अधिनियम की धारा **110** एफ के प्रावधानों पर विचार करते हुए, कानून की सामान्य नीति कार्यवाही की बहुलता और एक ही बिंदु पर निर्णयों के टकराव से बचने के लिए थी। न्यायालय की राय में, अधिनियम की धारा **110** में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए यह आवश्यक था कि मुआवजे के दावे को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जो दो अलग-अलग मंचों पर अलग-अलग सुनवाई योग्य हो। इसलिए, यह माना गया कि कार को नुकसान के संबंध में दावा भी ट्रिब्यूनल द्वारा सुनवाई योग्य था।

डॉ. ओम प्रकाश मिश्रा के मामले ***(1)***, *(*सुप्रा*)* में फैसले का पालन गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले *जोशी रतनसी गोपाजी बनाम गुजरात राज्य पठन परिवहन निगम और अन्य*[2] में किया गया था जिसमे यह देखा गया कि ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को धारा **110 (1)** में निर्दिष्ट किया गया था, जिसमें मुआवजे के दावों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित तीन शर्तों के अस्तित्व पर विचार किया गया था: -

(1) मुआवजे का दावा दुर्घटना के संबंध में होना चाहिए;

(2) दुर्घटना एक व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट से जुड़ी होनी चाहिए:

(3) यह मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होना चाहिए।

"मृत्यु या शारीरिक चोट से जुड़े" शब्दों को दुर्घटना के लिए सीमित माना गया था, न कि मुआवजे के दावों के लिए। एक सादे व्याकरणिक निर्माण पर, ट्रिब्यूनल द्वारा दावे पर निर्णय लिया जा सकता है जब यह दिखाया गया था कि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट शामिल थी जो मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न हुई थी। ऐसी दुर्घटना के संबंध में मुआवजे के लिए सभी प्रकार के दावे ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में थे। जहां तक ऐसी दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मुआवजे के दावों का संबंध है, धारा **110** को व्यापक आयाम का माना गया था और यह देखा गया था कि दुर्घटना में मृत्यु या शारीरिक चोट होने के बाद मुआवजे के दावे पर कोई सीमा नहीं लगाई गई थी। आगे यह देखा गया कि धारा में सीमित शब्द केवल दुर्घटना की प्रकृति के संबंध में थे और एक बार दुर्घटना निर्दिष्ट प्रकृति की साबित हो जाने के बाद, ऐसी दुर्घटना के संबंध में मुआवजे के लिए दावों की सभी श्रेणियों को ट्रिब्यूनल के समक्ष जाना था और उस हद तक अधिनियम की धारा **110** एफ के तहत सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया गया था। अदालत ऐसे मामले से नहीं निपट रही थी जहां एक वाहन में एक यात्री घायल हो गया था, लेकिन वह वाहन के मालिक से अलग था, जिसके पास संपत्ति के नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे के लिए एक अलग दावा था। यह देखा गया कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा अधिनियम की धारा **110 (1)** पर रखे जाने वाले अन्य निर्माण से चौंकाने वाले परिणाम होंगे क्योंकि घायल व्यक्ति या दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को दावे को विभाजित करना होगा और शारीरिक चोट या मृत्यु के संबंध में मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल जाना होगा और मुआवजे के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा। मोटर वाहन सहित संपत्ति की हानि या क्षति। कार्यवाही की बहुलता के अलावा, इससे अवांछनीय परिणाम और निर्णयों का टकराव होने की संभावना थी। यह देखा गया कि इस तरह के बेतुके परिणामों की ओर ले जाने वाले निर्माण से बचा जाना चाहिए। अपीलकर्ता के वकील की यह दलील कि विधायिका का इरादा ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को मृत्यु या शारीरिक चोट से जुड़ी दुर्घटनाओं तक सीमित करना था, को खारिज कर दिया गया और इन शब्दों को अकेले दुर्घटना का वर्णनात्मक माना गया था, न कि मुआवजे के दावे का।

(5) तथापि, *आर सेल्वाराज बनाम जगन्नाथन और अन्य*[3] न्यायालय के एकल पीठ के निर्णय में विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया है।। यह भी उसी मोटर दुर्घटना के दौरान हुई समग्र चोटों का मामला था और यह माना गया था कि ट्रिब्यूनल विशेष अधिकार क्षेत्र का एक न्यायाधिकरण था जिसका गठन केवल व्यक्तिगत चोटों और मृत्यु के संबंध में दावों पर निर्णय लेने के लिए किया गया था, न कि संपत्ति के नुकसान या क्षति के संबंध में। संपत्ति

2 1968 Accidents Claims Journal 338.
3 1969 ACJ 1

के संबंध में दावा केवल सिविल न्यायालय में सुनवाई योग्य माना गया था। न्यायाधीश डॉ. ओम प्रकाश मिश्रा के मामले **(1), (**सुप्रा**)** में डिवीजन बेंच के दृष्टिकोण को साझा करने में असमर्थ थे , कि जहां दावा एक समग्र था, इसका एक हिस्सा व्यक्तिगत चोटों के लिए मुआवजे से संबंधित था और बाकी संपत्ति के नुकसान से संबंधित था, ट्रिब्यूनल के पास पूरे मामले पर अधिकार क्षेत्र होगा। यह देखा गया कि यह सिद्धांत कि जहां राहत देने के लिए किसी अन्य विषय को एक अन्य विषय को कवर करना आवश्यक था, अन्यथा एक अलग मंच के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर केवल सिविल न्यायालयों पर लागू होता है और इसे विशेष अधिनियमों के तहत गठित विशेष न्यायाधिकरणों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह था कि ट्रिब्यूनल क़ानून का एक प्राणी था और इसका अधिकार क्षेत्र उस क़ानून की शर्तों द्वारा सख्ती से सीमित था। विशेष क्षेत्राधिकार के एक न्यायालय या न्यायाधिकरण को कानून के किसी भी सामान्य सिद्धांतों पर अपनी सीमाओं को पार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस क्षेत्राधिकार को इसकी वैधानिक परिभाषा के संदर्भ में सख्ती से सीमांकित किया जाना था। सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के संबंध में ऐसा नहीं था क्योंकि ये सिविल मामलों में सामान्य क्षेत्राधिकार के न्यायालय थे। शासन करने वाला सिद्धांत यह था कि सिविल न्यायालयों के पास सभी नागरिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा जब तक कि इसके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

(6) मेरे विचार से धारा **110 (1)** और **110** के ऑपरेटिव भागों को एक साथ पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए और यदि इनमें से किसी एक खंड के निर्माण में कोई संदेह या अस्पष्टता है, तो हम विधायिका के वास्तविक इरादों का पता लगाने के लिए दूसरे खंड के ऑपरेटिव भाग में उपयोग की जाने वाली भाषा पर भरोसा करने में बहुत गलत नहीं होंगे। 'मोटर दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों का अधिनिर्णयन' शब्द जिसमें मृत्यु या शारीरिक चोट शामिल है, को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और यह नहीं कहा जा सकता है कि 'मृत्यु या शारीरिक चोट से जुड़े' शब्द केवल दुर्घटना के प्रकार के लिए सीमित हैं, न कि मुआवजे के दावे के प्रकार के। यदि हम धारा **110 (1)** के ऑपरेटिव भागों को समग्र रूप से पढ़ते हैं, तो मुआवजे के लिए दावे जो ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में होंगे, केवल शारीरिक चोटों या मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में मुआवजे के दावे होंगे। ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिखता है कि इन शब्दों को एक भाग को योग्य बनाने के लिए क्यों लिया जाना चाहिए, लेकिन एक ही खंड के दूसरे भाग को नहीं। यहां तक कि अगर ये शब्द दो या दो से अधिक अस्पष्ट या अस्पष्ट व्याख्याओं को स्वीकार कर सकते हैं, तो हम धारा **110** ए **(1)** से मार्गदर्शन प्राप्त करने में पूरी तरह से उचित होंगे, जो उन व्यक्तियों की श्रेणियों के बारे में संपूर्ण प्रतीत हो सकता है जो ट्रिब्यूनल में दावा आवेदन कर सकते हैं। धारा **110** ए **(1)** के तीन खंडों में से किसी में भी मोटर दुर्घटना में संपत्ति के नुकसान या क्षति के कारण मुआवजे के दावे का सबसे दूर से संदर्भ नहीं है। इस उप-धारा के खंड हमें धारा **110** की उपधारा **(1)** के अस्पष्ट शब्दों की तुलना में विधायिका के वास्तविक इरादों का स्पष्ट संकेत दे सकते हैं। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ड्राफ्ट्समैन अधिनियम की धारा **110** ए **(1)** की तुलना में धारा **110 (1)** में विधायिका के वास्तविक इरादों को अधिक स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम रहा है। कानून के एक टुकड़े का मसौदा तैयार करने में कोई भी सावधानी या सहज प्रत्याशा भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की स्थितियों का प्रावधान नहीं कर सकती है और ड्राफ्ट्समैन की अनिश्चितताएं विधायिका के ध्यान में नहीं आ सकती हैं या न्यायालयों ने तब तक कानून की व्याख्या में कठिनाइयों की पेशकश करने वाली एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न नहीं की है। जब कभी ड्राफ्ट्समैन की चूक या खामियां प्रकाश में आती हैं, तो कानून की मरम्मत करने और उसे दुरुस्त करने के लिए समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। मोटर वाहन **(**संशोधन**)** अधिनियम **(1969** की संख्या **56)** द्वारा धारा **110** और **110** ए में व्यापक संशोधन किए गए हैं। धारा **110 (1)** में किए गए संशोधनों द्वारा, ऐसी मोटर दुर्घटनाओं में तीसरे पक्ष की किसी भी संपत्ति को नुकसान के दावों को भी ट्रिब्यूनल के समक्ष प्राथमिकता दी जा सकती है। मेरे विचार से, धारा **110 (1)** में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कुछ तदनुरूपी संशोधन धारा **110** ए **(1)** के खंडों में किए जाने चाहिए थे, जो उन व्यक्तियों की श्रेणी की एक विस्तृत सूची देने के लिए माना जाता है, जो अधिनियम के तहत दावा आवेदन दायर कर सकते हैं। यदि मोटर वाहन सहित अपनी संपत्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाने वाले तीसरे पक्ष को ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा दायर करने का अधिकार

दिया जाना है, तो अधिनियम की धारा **110** ए में एक खंड होना चाहिए जिसके तहत उस दावे को तीसरे पक्ष द्वारा दायर किया जा सकता था, जो मोटर दुर्घटना में खोई या क्षतिग्रस्त संपत्ति का मालिक था। जहां तक वर्ष **1963** में हुई एक मोटर दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के दावे से संबंधित इस मामले के निर्णय का संबंध है, वर्ष **1969** में अधिनियम में किए गए संशोधनों से हमें रोकना नहीं चाहिए। फोरम का चुनाव और दावा आवेदन की प्रस्तुति अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होनी चाहिए क्योंकि वे दुर्घटना के समय प्रबल थे और दावा दायर करने और पांच या छह साल से अधिक समय बाद किए गए संशोधनों का मामले पर कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(7) डॉ. ओम प्रकाश मिश्रा के मामले **(**एआईआर **1962,** एमपी **19)** में अधिनियम की धारा **110 (1)** के ऑपरेटिव भागों पर रखी गई व्याख्या कुछ अतार्किक निष्कर्षों को जन्म दे सकती है। यदि शब्द 'मृत्यु या शारीरिक चोट से जुड़े' केवल दुर्घटना के प्रकार के लिए सीमित हैं और समग्र चोटों से जुड़ी ऐसी दुर्घटनाओं से उत्पन्न मुआवजे के दावे के नहीं हैं, तो यह महत्वहीन प्रतीत हो सकता है कि क्या उसकी संपत्ति के नुकसान या क्षति से पीड़ित व्यक्ति एक ही व्यक्ति था, जिसे व्यक्तिगत चोट लगी थी या मोटर दुर्घटना में चोट या मृत्यु को बनाए रखने वाले व्यक्ति से अलग व्यक्ति था। यदि ऐसी समग्र चोटों के संबंध में मुआवजे के लिए सभी दावों को ट्रिब्यूनल को प्राथमिकता दी जानी है, तो अपनी संपत्ति के नुकसान या क्षति से पीड़ित व्यक्ति, चाहे वह शारीरिक चोट से पीड़ित व्यक्ति के समान या अलग हो, को अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा दायर करना होगा और यह एकमात्र तरीका है जिसमें कार्यवाही की बहुलता या निर्णयों का टकराव हो सकता है। बचा। कार्यवाही की बहुलता और निर्णयों के टकराव से बचने की इस इच्छा को डॉ. ओम प्रकाश मिश्रा (1), और जोशी रतनसी गोपाजी (2) के मामलों में निष्कर्ष पर आने के लिए मुख्य तर्क के रूप में दिया गया था कि समग्र चोट के मामले में संपत्ति की क्षति या हानि के संबंध में दावा भी ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में होगा। यदि अपनी संपत्ति के नुकसान या क्षति से पीड़ित व्यक्ति उस व्यक्ति से अलग व्यक्ति है, जिसे चोट लगी है या मृत्यु हुई है, तो अधिनियम की धारा 110 ए (एल) में कोई खंड नहीं है जिसके तहत अपनी संपत्ति के नुकसान या क्षति से पीड़ित व्यक्ति अपना दावा आवेदन दायर कर सकता है। यह एक असंगत स्थिति होगी।

(8) मेरे विचार से अधिनियम की धारा 110ए (1) के विभिन्न खंड इस तथ्य का कहीं अधिक स्पष्ट संकेत देते हैं कि मोटर दुर्घटना में हुई संपत्ति के नुकसान या क्षति के दावे, चाहे इससे शारीरिक चोट लगी हो या नहीं, अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। हालांकि, मामला संदेह से मुक्त नहीं है। चूंकि यह प्रश्न बड़ी संख्या में मामलों में उठने की संभावना है, इसलिए यह वांछनीय है कि इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा इस प्रश्न पर एक आधिकारिक निर्णय होना चाहिए। इस न्यायालय के किसी भी निर्णय को, जिसकी रिपोर्ट नहीं की गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है, मेरे ध्यान में नहीं लाया गया है और अन्य उच्च न्यायालयों के बीच विचारों का टकराव है। यह वांछनीय है कि इस विषय पर इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ का एक आधिकारिक निर्णय होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ समय के लिए मैदान को आयोजित करने की बेहतर संभावना होगी। इस विषय पर केस लॉ में बार-बार परिवर्तन करने से दावेदारों को कठिनाई हो सकती है और कुछ मामलों में मोटर वाहनों सहित संपत्ति को मोटर दुर्घटना में नुकसान या क्षति के संबंध में किसी व्यक्ति को पूरे दावे से वंचित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश II, नियम 2 की सीमा की सीमा हो सकती है।

(9) अत, इस मामले को बड़ी पीठ के गठन के संबंध में आदेश के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता है ताकि कानून के इस प्रश्न पर इस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए अधिकारपूर्वक निर्णय लिया जा सके और जहां तक हमारा संबंध है, विचारों के टकराव को समाप्त किया जा सके।

डिवीजन बेंच का आदेश

न्यायमूर्ति सी. जी. सूरी, -(10) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका को वापस करने के चंडीगढ़ के उप-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ यह पहली अपील मेरे सामने तब आई जब मैं एकल पीठ में

अकेला बैठा था। कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के बीच विचारों के टकराव और हमारे स्वयं के मुद्दे पर निर्णय के अभाव को देखते हुए, मैंने मामले को एक बड़ी पीठ के निर्णय के लिए भेजा था। इस प्रकार यह अपील हमारे समक्ष आई है।

(11) इस मामले के तथ्य दिए गए हैं और उपलब्ध निर्णयों पर मेरे दिनांक 4 मई, 1970 के संदर्भ क्रम में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसे इस निर्णय के एक भाग के रूप में पढ़ा जा सकता है। मैंने उस संदर्भ क्रम में संक्षेप में संकेत दिया था कि मैं आर सेल्वाराज बनाम मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तैयार हूं, हालांकि बिल्कुल समान कारणों से नहीं । जगन्नाथ और एक अन्य (3), भले ही यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के विचारों के विपरीत था, डॉ. ऑर्न प्रकाश मिश्रा बनाम नेशनल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और अन्य *(1)*, और जोशी रतनसी गोपाजी बनाम गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम और दूसरा (2)। आर. सेल्वाराज के मामले (3) में, न्यायालय यह मानता है कि ट्रिब्यूनल केवल व्यक्तिगत चोटों और मृत्यु के संबंध में दावों पर निर्णय लेने के लिए गठित विशेष अधिकार क्षेत्र का न्यायालय था, न कि संपत्ति के नुकसान या क्षति के संबंध में। न्यायालय इस आधार पर एक विशेष अधिनियम के तहत गठित एक विशेष न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के खिलाफ था कि अधिकार क्षेत्र कानून की शर्तों द्वारा सख्ती से सीमित था। गुजरात और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों द्वारा अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने वाले दो निर्णयों में, माननीय न्यायाधीशों का निश्चित मत था कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा मुआवजे के दावे के निर्धारण के लिए सभी शर्तें मोटर दुर्घटना के मामले में संतुष्ट थीं, जहां व्यक्तियों और संपत्ति को चोट लगी थी; इन न्यायालयों द्वारा समग्र चोटों के मामलों के रूप में वर्णित। यदि यह पता चलने के बाद कि मामला पूरी तरह से क़ानून के पत्र के भीतर आता है, न्यायालयों ने कार्यवाही की बहुलता या निर्णयों के टकराव से बचने की वांछनीयता का उल्लेख करके औचित्य और नीति के आधार पर सहायता की, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय विशेष ट्रिब्यूनल का गठन करने वाले क़ानून की शर्तों के भीतर मामले को लाए बिना केवल एक विशेष ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि औचित्य और नीति को एक दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त विचार के रूप में लाया गया है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों की राय में वैधानिक प्रावधानों के शाब्दिक निर्माण द्वारा समर्थित था।

(12) हमें यह मानना होगा कि विधायिका कभी भी यह इरादा नहीं रखती है कि उसकी भाषा दो अर्थों को व्यक्त करेगी या दोहरे निर्माण को स्वीकार करेगी और आम तौर पर यह केवल न्यायालयों की अप्रत्याशित सरलता या उनके विचारों की उर्वरता है कि एक क़ानून द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा दो अस्पष्ट व्याख्याओं को जन्म देती है। मैं पहले ही यह राय व्यक्त कर चुका हूं कि ऐसे मामले में न्यायालय विधायिका के वास्तविक इरादों का पता लगाने के लिए क़ानून में पूरक प्रावधानों को देखने के हकदार होंगे। मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110 (1) और 110 ए (1) पूरक प्रावधान हैं और यदि एक खंड के कुछ हिस्से दो अस्पष्ट व्याख्याओं को जन्म दे सकते हैं, तो हम धारा 110 ए (1) के प्रावधानों को देख सकते हैं, जो अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा विचार किए जा सकने वाले मुआवजे के दावों के प्रकार के बारे में विस्तृत प्रतीत हो सकते हैं।

(13) राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायाधिकरणों के गठन का प्रावधान पहली बार मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम (1956 की संख्या 100) द्वारा अधिनियम में किया गया था। इन संशोधनों को करने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण और विधेयक के विभिन्न खंडों पर नोट्स हमें इन संशोधनों को बनाने में विधायिका के इरादों का पता लगाने में सक्षम बनाएंगे। 1955 का बिल नंबर 57, जिसे विधिवत संसाधित किया गया था और मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 100) के रूप में अधिनियमित किया गया था, 12 नवंबर, 1955 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II-धारा 2 में प्रकाशित किया गया था। उद्देश्यों और कारणों का कथन पृष्ठ 624 से 626 पर दिखाई देता है और प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

"(5) राज्य सरकारों को मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट से संबंधित दुर्घटनाओं के मामलों में क्षति का निर्धारण करने और आदेश देने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करने और दिए गए नुकसान के भुगतान के संबंध में बीमाकर्ता की देयता पर निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में, दावों को पूरा करने के लिए बीमा कंपनी के दायित्व को लागू करने से पहले एक अदालत डिक्री प्राप्त करनी होती है। संशोधन को मोटर वाहनों के कारण चोट या मृत्यु के कारण दावों को प्राथमिकता देने में सीमित साधनों वाले व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली मौजूदा कठिनाई को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(14) इसके अतिरिक्त, विधेयक के विभिन्न खण्डों पर विचार करते समय, खंड **80** और **82** पर टिप्पणियां, जिनमें धारा **110** को प्रतिस्थापित किया गया था और कतिपय अन्य धाराएं जोड़ी गई थीं, निम्नानुसार हैं -

खंड **80** और **82**

मौजूदा धारा **110** के तहत, मोटर दुर्घटनाओं की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई हैं, लेकिन इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों को संबंधित बीमा कंपनी की स्पष्ट इच्छा को छोड़कर, बीमाकर्ता की देयता या दी जाने वाली क्षति की राशि पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इस प्रावधान ने चोट या मृत्यु के कारण दावों को प्राथमिकता देने में सीमित साधनों वाले व्यक्तियों की मदद नहीं की है, क्योंकि दावों को पूरा करने के लिए बीमा कंपनी के दायित्व को लागू करने से पहले एक अदालत की डिक्री प्राप्त करनी होगी। इसलिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य सरकारों को क्षति का निर्धारण करने और अधिनिर्णय देने के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नियुक्त करने का अधिकार दिया जाए। इन खंडों में संशोधन आवश्यक प्रावधान करते हैं।

(15) उद्देश्यों और कारणों के कथन से संबंधित उद्धरण के शुरुआती वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट से संबंधित दुर्घटनाओं के मामलों में नुकसान का निर्धारण करने और देने के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की जा रही थी। बाद के हिस्सों में जहां भी शब्द "चोट या मृत्यु" होते हैं, वे स्पष्ट रूप से उसी संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं और कानूनी अर्थों में 'चोट' शब्द के दायरे को बढ़ाने का इरादा नहीं रखते हैं ताकि संपत्ति की चोट को शामिल किया जा सके जैसा कि मनुष्यों को चोट या उनकी मृत्यु से अलग है। 'मृत्यु' शब्द के साथ-साथ 'चोट' शब्द का उपयोग एक और संकेत है कि केवल शारीरिक चोट कानून के चिंतन के भीतर थी। इसके अलावा, विधेयक के प्रासंगिक खंडों पर उद्देश्यों और कारणों और नोट्स के विवरण में यह इंगित किया गया है कि संशोधन सीमित साधनों के व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। अपने वाहनों या संपत्ति को नुकसान के संबंध में मोटर वाहनों के मालिक समुदाय के अमीर वर्गों के दावे स्पष्ट रूप से विधायिका के विचार में नहीं थे।

(16) अधिनियम की धारा 110 (1) में "मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न व्यक्तियों की मृत्यु, या शारीरिक चोट से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के लिए दावे" वाक्यांश की व्याख्या या निर्माण सभी परेशानी का कारण प्रतीत हो सकता है। कानून जो क्षतिपूर्ति करना चाहता है वह दुर्घटना नहीं है, बल्कि परिणामी चोट है। एक घटना या घटना, चाहे वह असामान्य या गंभीर हो, दुर्घटना से कम हो जाएगी यदि इससे कोई चोट नहीं लगती है, चाहे वह किसी व्यक्ति या संपत्ति को हो। यह हमेशा चोट होती है जिसकी भरपाई की जाती है और कानून द्वारा दुर्घटना की भरपाई का कोई सवाल ही नहीं है। मुआवजा शब्द एक अर्थ उत्पन्न करता है जो ऊपर पुन: प्रस्तुत वाक्यांश की पूरी लंबाई के माध्यम से प्रतीत हो सकता है और वाक्यांश के बीच में "दुर्घटना" शब्द से मिलते ही उत्पन्न आवेग के अचानक समाप्त होने का कोई सवाल नहीं है। मुआवजा शब्द हमेशा उस चोट को दर्शाता है जिसे क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है और इस शब्द का दुर्घटना के प्रकार को योग्य बनाने का कोई सवाल नहीं है। यह शब्द मेरे दिमाग को यह स्पष्ट करता है कि क्षतिपूर्ति की जाने वाली चोट शारीरिक चोट या मृत्यु है और यह

अर्थ धारा 110 ए (1) द्वारा और स्पष्ट किया गया है जो संपत्ति को नुकसान या चोट के संबंध में किसी भी दावे के मनोरंजन का प्रावधान नहीं करता है।

(17) इसलिए, मेरा विचार है कि वाद-पत्र को ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा गलत तरीके से लौटा दिया गया था।

(18) अपील सफल होने के योग्य है और चंडीगढ़ के उप-न्यायाधीश को मुकदमे पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 10 के आदेश VII के तहत वाद लौटाने के उनके आदेश को रद्द किया जाता है। प्रतिवादी-प्रतिवादी इस स्तर तक मुकदमे बाजी की अपीलकर्ता की लागत का भुगतान करेंगे। इसके बाद की कार्यवाही के लिए लागत घटना का पालन करेगी। पक्षकारों को 16 अक्तूबर, 1970 को आगे के निर्देशों के लिए चंडीगढ़ में वरिष्ठ उप-न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होना चाहिए।

न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला,.- सहमत ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के समिति उपयोग कि लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा